राष्ट्रीय · National

सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला, जल जीवन मिशन 2.0 और नशा मुक्त भारत अभियान

सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने ध्वस्तीकरण पर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तय किए, जल जीवन मिशन 2.0 का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ और नशा मुक्त भारत अभियान 35 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा।

राष्ट्रीय · National

1. बुलडोजर कार्रवाई पर SC का फैसला

- कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर संपत्ति नहीं गिरा सकती; सामूहिक दंड असंवैधानिक।
- ध्वस्तीकरण से पहले 15 दिन का अग्रिम नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य।
- अवैध ध्वस्तीकरण पर अधिकारी अवमानना के दोषी होंगे और हर्जाना भरेंगे।

राष्ट्रीय · National

2. जल जीवन मिशन 2.0 क्षेत्रीय सम्मेलन

- तिरुचिरापल्ली में 7 दक्षिणी राज्यों/UTs का क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न।
- बुनियादी ढांचे के साथ-साथ जल स्रोतों की संधारणीयता और O&M पर मुख्य जोर।
- ग्राम पंचायतों और पानी समितियों को जल प्रबंधन का पूर्ण दायित्व।

राष्ट्रीय · National

3. नशा मुक्त भारत अभियान का विस्तार

- अभियान ने 35.88 करोड़ से अधिक नागरिकों तक जागरूकता पहुंचाई।
- 14.35 करोड़ युवा और 11.33 करोड़ महिलाएं अभियान से सीधे जुड़ीं।
- देश भर में 198 जिला नशा मुक्ति केंद्र (DDAC) सक्रिय रूप से कार्यरत।

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

सुप्रीम कोर्ट पीठ के सदस्य	न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन
ध्वस्तीकरण से पूर्व अनिवार्य नोटिस अवधि	15 दिन
JJM 2.0 क्षेत्रीय सम्मेलन स्थल	तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
मूल जल जीवन मिशन का लक्ष्य	55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (lpcd)
नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ	15 अगस्त 2020
वर्तमान में संचालित जिला नशा मुक्ति केंद्र (DDAC)	198 केंद्र

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनधिकृत संपत्तियों के ध्वस्तीकरण (बुलडोजर कार्रवाई) से पहले कम से कम कितने दिनों का कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य किया है?

A 7 दिन

B 10 दिन

C 15 दिन

D 30 दिन

उत्तर / Answer: C — सर्वोच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ध्वस्तीकरण से पूर्व पंजीकृत डाक द्वारा 15 दिन का अग्रिम कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य किया है।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

सुप्रीम कोर्ट ने किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनमाने ध्वस्तीकरण पर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश जारी किए?

A अनुच्छेद 32

B अनुच्छेद 136

C अनुच्छेद 142

D अनुच्छेद 226

उत्तर / Answer: C — सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों में पूर्ण न्याय (Complete Justice) करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत इन बाध्यकारी दिशा-निर्देशों को लागू किया है।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends